



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 159]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 1976/चैत्र 10, 1898

No. 159]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 1976/CHAITRA 10, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 30th March 1976

S.O. 260(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) No. S.O. 1482 dated the 31st March, 1971, read with the Order of the Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies No. S.O. 184(E) dated 9th March, 1976 the management of the Industrial Undertaking known as Messrs. Gresham and Craven of India Private Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) has been taken over under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period upto and inclusive of the 31st day of March, 1977;

And whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 555(E) dated the 14th August, 1972 (hereinafter referred to as the said Order), read with the orders of the Government of India in the late Ministry of Heavy Industry Nos. S.O. 436(E) dated the 10th August, 1973, 490(E) dated the 9th August, 1974 and 434(E) dated the 14th August, 1975, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the said Act, declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force to which the said industrial undertaking was a party or which may be applicable to it immediately before the 31st day of March, 1971, shall remain suspended upto the 30th of March, 1976.

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended by a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order by a further period of one year upto the 30th of March, 1977,

[No. 4/8/76-CUC.]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1976

का० आ० 260 (अ).—भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 184 (अ) तारीख 9 मार्च, 1976 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 1482 तारीख 31 मार्च, 1971 द्वारा मेसर्स ग्रेशम एण्ड क्रेवन आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 के अधीन 31 मार्च, 1977 तक की अवधि के लिए, जिसमें यह दिन भी है, ग्रहण कर लिया गया है।

और, भारत सरकार के भूतपूर्व भारी उद्योग मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 436 (अ) तारीख 10 अगस्त, 1973, 490 (अ) तारीख, 9 अगस्त, 1974 और 434 (अ) तारीख 14 अगस्त, 1975 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 555 (अ) तारीख, 14 अगस्त, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 18 च ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषित किया है कि ऐसी सभी प्रवृत्त संविदाएं, सम्पत्ति के हस्तान्तरणपत्र, करार, समझौते, पंचाट, स्थायी आदेश, या अन्य लिखित जिनका कि उक्त औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार था या जो 31 मार्च, 1971 से ठीक पूर्व उसे लागू थे, 30 मार्च, 1976 तक निलम्बित रहेंगे।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की कालावधि एक वर्ष के लिए और बढ़ा देनी चाहिए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश की कालावधि एक और वर्ष के लिए अर्थात् 30 मार्च 1977 तक बढ़ाती है।

[सं० 4/8/76—सी यूसी]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव।